Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अप्रैल 2024 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- डुमक गाँव को 8 महीने में मिलेगी सड़क 3
- गंगोत्री धाम में बर्फबारी 4
- उत्तराखंड आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिये हेलीकॉप्टर सेवा 5
- ल्यूमिनस ने उत्तराखंड में सौर मॉड्यूल सुविधा में निवेश किया 5
- उत्तराखंड में ली-आयन बैटरियों और ई-अपशिष्ट के लिये पुनर्चक्रण सुविधा 6
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा 7
- अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगाँठ 8
- भ्रामक पतंजलि विज्ञापनों पर उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण 9
- उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष 9
- चारधाम यात्रा 11
- सीमा पार आवागमन पर रोक 12
- उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण 13
- उत्तराखंड में हताहत-मुक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी 13
- उत्तराखंड में सद्भावना सम्मेलन 14
- उत्तराखंड में रिकॉर्ड 55% मतदान 15
- उत्तराखंड में देहरादून हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू 17
- उत्तराखंड की मानसखंड कॉरिडोर यात्रा 17
- राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर 18
- चिपको आंदोलन के 50 वर्ष 18
- उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना 20
- उत्तराखंड में पिघलते ग्लेशियर 21
- उत्तराखंड मॉनसून वर्षा के लिये तैयार 22
- नैनीताल में वनाग्नि 22
- उत्तराखंड ने पतंजलि उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया 23

नोट :

उत्तराखंड

डुमक गाँव को 8 महीने में मिलेगी सड़क

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर स्थित चमोली ज़िले के डुमक और अन्य गाँवों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क, जो 17 वर्षों से विलंबित है, इस वर्ष के अंत से पहले पूरी हो जाएगी।

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के मुताबिक डुमक में कुछ मतदाताओं ने सड़क निर्माण में लगातार हो रही देरी से तंग आकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
- **उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (URRDA)** के CEO ने एक बयान जारी कर कहा कि सड़क का बचा हुआ कार्य अगले आठ महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
  - एजेंसी राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन और मानदंडों के तहत **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के एकमात्र उद्देश्य के लिये कार्य करेगी।**

भारत-चीन सीमा

- भारत और चीन के बीच की सीमा अपने पूरे भाग में स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है तथा कुछ हिस्सों में **वास्तविक नियंत्रण रेखा** पर कोई पारस्परिक सहमति भी नहीं है।
- LAC **वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आया।**
- भारत-चीन सीमा को तीन सेक्टरों/क्षेत्रों में बाँटा गया है:
  - **पश्चिमी क्षेत्र:** लद्दाख
  - **मध्य क्षेत्र:** हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
  - **पूर्वी क्षेत्र:** अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम

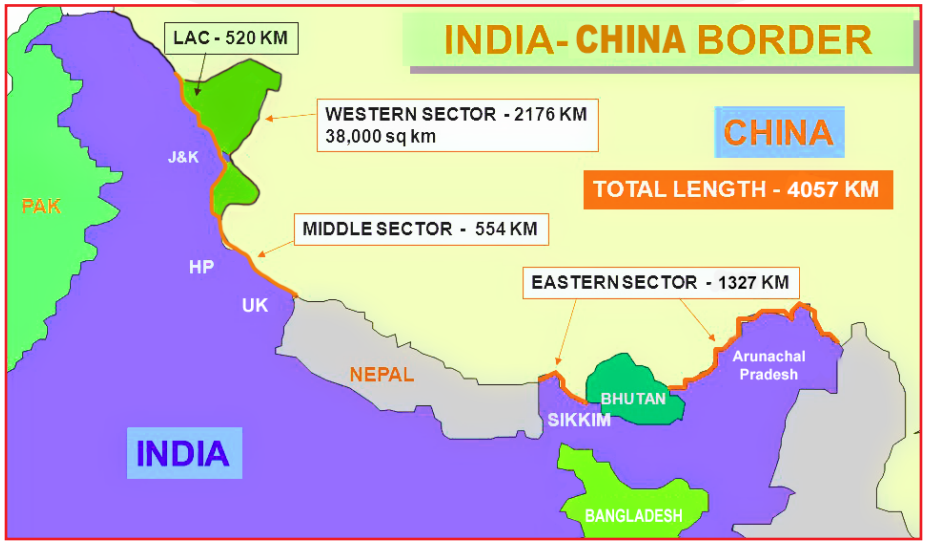

नोट :

गंगोत्री धाम में बर्फबारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड में देवी गंगा को समर्पित सबसे ऊँचे मंदिर गंगोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी हुई।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन ज़िलों और लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों के लिये अलर्ट जारी किया था।

मुख्य बिंदु:

- **गंगोत्री मंदिर** जहाँ **देवी गंगा** की पूजा की जाती है, 20 फीट की ऊँचाई पर स्थित है और **सफेद ग्रेनाइट** पर उत्कृष्ट नक्काशी का दावा करता है।
- **यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है और उत्तराखंड के चार धाम तीर्थस्थलों में से एक है।**
- चार धाम यात्रा में शामिल अन्य तीर्थस्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री हैं।
- नदी को उद्गम स्थल पर **भागीरथी** कहा जाता है और देवप्रयाग से आगे जहाँ यह अलकनंदा से मिलती है, इसका नाम गंगा हो जाता है।
- **पवित्र नदी का उद्गम गोमुख में है,** जो गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है और गंगोत्री से 19 किमी. की दूरी पर है।

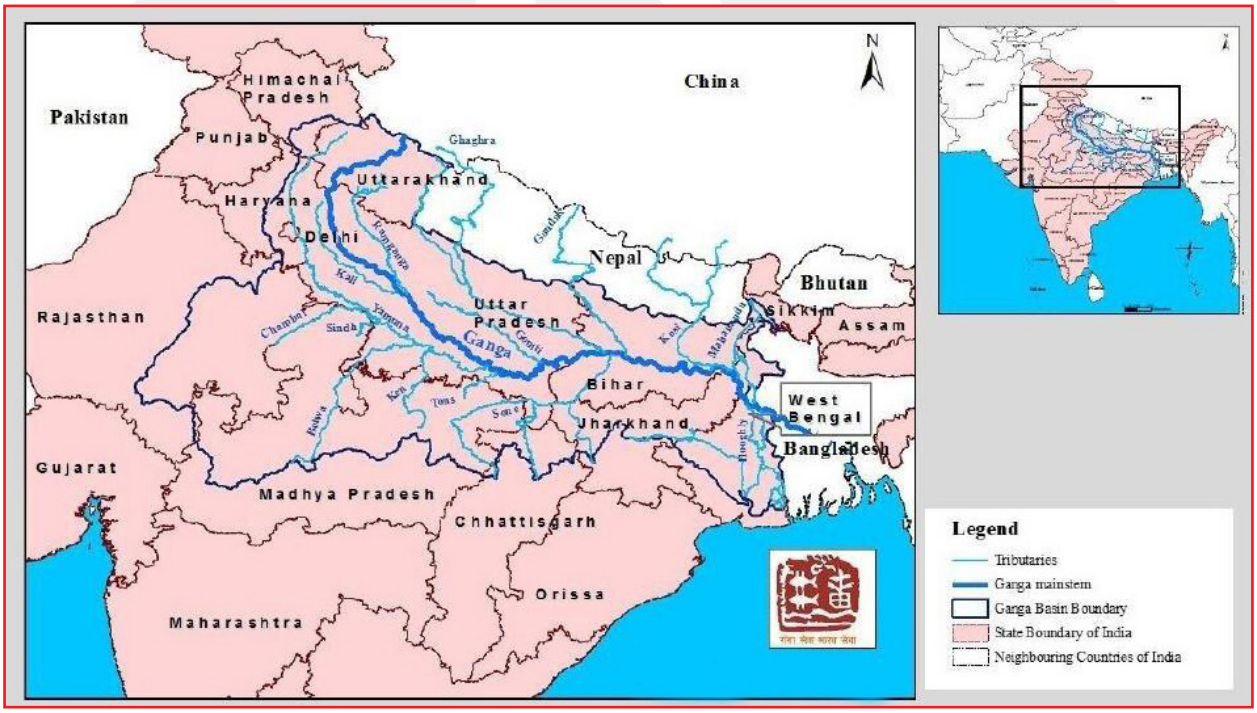

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- IMD **की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।** यह देश की **राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है** और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
- IMD **विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।**

नोट :

उत्तराखंड आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिये हेलीकॉप्टर सेवा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में नैनी सैनी हवाई अड्डे से आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड सरकार की **हेली दर्शन योजना** के तहत, एक Mi-19 हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रियों को हवाई अड्डे से व्यास घाटी क्षेत्र में आदि कैलाश और ओम पर्वत तक ले जाएगा तथा शिखर पर चढ़ने के बाद वापस लौटेंगा।
  - इस सेवा का शुभारंभ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया।

आदि कैलाश

- इसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंगकोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है।

ल्यूमिनस ने उत्तराखंड में सौर मॉड्यूल सुविधा में निवेश किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया।

- ल्यूमिनस ने कनेक्टेड ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करने वाले अपने सौर पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने हेतु संयंत्र में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर भी लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु:

- **1.2 अरब रुपए** के शुरुआती निवेश से निर्मित पूरी तरह से स्वचालित **10 एकड़ का संयंत्र 1 गीगावॉट क्षमता** तक विस्तार योग्य है।
- यह लॉन्च ल्यूमिनस के लिये केवल सोलर इनवर्टर और बैटरी बनाने वाली कंपनी से अब सोलर मॉड्यूल बनाने की कंपनी में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है।

नोट :

- कंपनी यह भी दावा करती है कि वह एकमात्र भारतीय फर्म है जो संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली डिज़ाइन तथा निर्माण कर सकती है।
- यह सुविधा **आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि आवश्यकताओं के लिये 5BB (बसबार्स) से 16BB कॉन्फ़िगरेशन** तक अनुकूलनशीलता के साथ पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, एन-प्रकार तथा **TOPCon सौर पैनलों** का उत्पादन करेगी।
- कंपनी ने **सौर मॉड्यूल प्रौद्योगिकी विकास के लिये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय** के साथ साझेदारी की है।
- यह लॉन्च सरकार के 'मेक इन इंडिया' मिशन और हाल ही में घोषित **'पीएम सूर्य घर: मुफ्त विद्युत योजना'** सौर कार्यक्रम के अनुरूप है।
- मूल रूप से **1 करोड़ घरों में 1-3 किलोवाट (किलोवाट) सौर प्रणालियों की स्थापना पर पूरी तरह से सब्सिडी** देने का इरादा था, यह योजना अब लागत का 60% तक कवरेज प्रदान करती है, परिवारों को शेष राशि को पूरी करने की आवश्यकता होती है, भले ही सुलभ ऋण के साथ।
- इस योजना में हर महीने **300 यूनिट तक मुफ्त** विद्युत उत्पन्न करने की परिकल्पना की गई है, जिससे परिवारों को सालाना 15,000-18,000 रुपए का लाभ होगा।
- मेरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा हाल ही में जारी "भारत में सोलर पीवी विनिर्माण की स्थिति 2024" रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 20.8 गीगावॉट सौर मॉड्यूल और 3.2 गीगावॉट सौर सेल क्षमता जोड़ी।

उत्तराखंड में ली-आयन बैटरियों और ई-अपशिष्ट के लिये पुनर्चक्रण सुविधा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने उत्तराखंड के सितारगंज (ज़िला उधम सिंह नगर) में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ली बैटरी और ई-कचरे की रीसाइक्लिंग हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिये मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है

मुख्य बिंदु:

- इस समझौते के माध्यम से, TDB ने 15 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से ₹7.5 करोड़ की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है, जो **सतत् विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - ली-आयन बैटरियों का कुशल पुनर्चक्रण देश के भीतर सेल निर्माण के लिये द्वितीयक कच्चे माल के एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है।
  - खर्च की गई **लिथियम-आयन बैटरियों (LIB)** के निपटान से उत्पन्न होने वाले ई-कचरे का बढ़ता आयात पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उनके बढ़ते उपयोग से प्रेरित है।
  - लैंडफिलिंग और भस्मीकरण के माध्यम से LIB का निपटान पर्यावरण तथा सुरक्षा चिंताओं को उत्पन्न करता है, जो रीसाइक्लिंग पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है
  - खर्च किये गए LIB से धातुओं की पुनर्प्राप्ति के माध्यम से मूल्य सृजन की संभावना ने इन बैटरियों द्वारा उत्पन्न ई-कचरे के पुनर्चक्रण में रुचि बढ़ा दी है।
- लिथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग बाज़ार का आकार **वर्ष 2030 तक 14.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें 21.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) है, जो वर्ष 2021** में 3.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- इसके बावजूद, **95% ली-आयन बैटरियाँ वर्तमान में लैंडफिल में समाप्त हो जाती हैं, जबकि केवल 5%** रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग से गुजरती हैं।
- ई-अपशिष्ट परिदृश्य में अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व का प्रतिकूल पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- बैटरी अपशिष्ट के बढ़ते मुद्दे को संबोधित करने, महत्त्वपूर्ण तत्त्वों से संबंधित प्रवासी आपूर्ति पक्ष के जोखिमों को कम करने और कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिये कुशल व पर्यावरण के अनुकूल रीसाइक्लिंग विधियाँ आवश्यक हैं।
- ई-अपशिष्ट उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है।

लि-आयन बैटरी

- 'लिथियम-आयन बैटरी' अथवा 'लि-आयन' बैटरी एक प्रकार की **रिचार्जेबल (पुन: चार्ज की जा सकने वाली) बैटरी है।**
- लि-आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जबकि **एक नॉन-रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में धातु सदृश लिथियम का उपयोग किया जाता है।**
- एक बैटरी में वैद्युत अपघट्य (Electrolyte) दो इलेक्ट्रोड होते हैं। **वैद्युत अपघट्य के कारण आयनों का संचरण होता है।**
- बैटरी के **डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं**, जबकि **चार्ज होते समय विपरीत दिशा में।**

ई-अपशिष्ट

- **इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट),** एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग **सभी प्रकार के पुराने, खराब हो चुके या बेकार पड़े बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों,** जैसे घरेलू उपकरण, कार्यालय सूचना तथा संचार उपकरण आदि का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
- भारत में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये कानून वर्ष 2011 से लागू हैं, जिसके अनुसार केवल अधिकृत विखंडनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्त्ता ही ई-अपशिष्ट एकत्र करते हैं। **ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 2017 में अधिनियमित किया गया था।**
- घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से अपशिष्ट को अलग करने, प्रसंस्करण एवं निपटान के लिये भारत का पहला ई-अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य बिंदु:

- याचिका में **उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3(1)** को चुनौती देते हुए कहा गया है कि राज्य की महिलाओं के लिये 30% आरक्षण **भारत के संविधान के** अनुच्छेद 16 के दायरे से बाहर है।
- मामले के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने **14 मार्च 2024 को प्रांतीय सिविल सेवा (PCS)** के विभिन्न पदों के लिये विज्ञापन जारी किया था।
  - **विज्ञापन के खंड 10 (d)** में उत्तराखंड की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिये 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
  - याचिकाकर्त्ता ने आरक्षण को चुनौती दी और कहा कि केवल मूल निवास के आधार पर क्षैतिज आरक्षण नहीं किया जाना चाहिये।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3(1) असंवैधानिक है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 16

- लोक नियोजन के विषय में सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण का आधार प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 16(4)** में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे **पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान** कर सकता है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

नोट :

- **अनुच्छेद 16(4A)** में प्रावधान है कि राज्य **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण** के लिये कोई भी प्रावधान कर सकता है यदि उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
- **अनुच्छेद 16(6)** में प्रावधान है कि राज्य किसी भी **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण** के लिये कोई उपबंध कर सकता है।

अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में रामकृष्ण मठ और मिशन का केंद्र, मायावती में अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगाँठ मनाई गई

- इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में हाल ही में मायावती में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने **वर्ष 1899** में की थी।
- आश्रम का उद्देश्य अनुष्ठानिक परंपराओं से मुक्त **अद्वैत दर्शन का अध्ययन, अभ्यास और प्रचार** करना है तथा इसका प्रसार करने में दूसरों को प्रशिक्षित करना भी है।
  - थोड़े ही समय में आश्रम पूर्व और पश्चिम के सर्वोत्तम विचारधाराओं का केंद्र बिंदु बन गया। इसने मूल अद्वैत सिद्धांत का प्रसार करने में मदद की।
- कोलकाता में अद्वैत आश्रम की स्थापना इसके **प्रकाशनों** और पत्रिका '**प्रबुद्ध भारत**' की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये मायावती आश्रम के 21 वर्ष बाद की गई थी।
- अद्वैत वेदांत हिंदू धर्म का मूल है, जो मानव जाति के अस्तित्त्व और एकजुटता की शिक्षा देता है।
  - पिछले 125 वर्षों से अद्वैत आश्रम अपनी कोलकाता शाखा से प्रकाशित साहित्य के माध्यम से अद्वैत विचारधारा के सिद्धांतों का प्रसार कर रहा है।

अद्वैत वेदांत

- यह शुद्ध अद्वैतवाद की एक दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करता है, एक पुनरीक्षण विश्वदृष्टि जो यह **प्राचीन उपनिषद ग्रंथों** से संबद्ध है।
- अद्वैत वेदांतियों के अनुसार, उपनिषद् अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं जिसे 'ब्रह्म' कहा जाता है, जो सभी वस्तुओं की वास्तविकता है।
- अद्वैतवादी **ब्रह्म को व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता से परे** समझते हैं। वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि **किसी व्यक्ति का मूल (आत्मन) ब्रह्म** है।
- अद्वैत वेदांत का मूल ज़ोर यह है कि **आत्मा शुद्धाद्वैत/ शुद्ध अनैच्छिक चेतना** है।
- यह बिना किसी द्वितीय, अद्वैत, अनंत अस्तित्त्व वाला और संख्यात्मक रूप से ब्रह्म के समान है।

स्वामी विवेकानंद

- उनका जन्म **12 जनवरी, 1863 को नरेंद्र नाथ दत्त** के रूप में हुआ था।
- वह एक **साधु और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य** थे।
- उन्होंने **वेदांत और योग** के भारतीय दर्शन को पश्चिमी विश्व में पेश किया तथा उन्हें अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने, 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है।
- उन्होंने **वर्ष 1987 में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस** के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। संस्था ने भारत में व्यापक शैक्षणिक और परोपकारी कार्य किये।
- उन्होंने **वर्ष 1893 में शिकागो (U.S.) में आयोजित प्रथम धर्म संसद** में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

नोट :

भ्रामक पतंजलि विज्ञापनों पर उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी (SLA) को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों को हल करने में विफलता के लिये फटकार लगाई है, जो दो वर्ष से अधिक समय से जारी थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निष्क्रियता के लिये SLA के नवीनतम औचित्य को खारिज़ कर दिया।

मुख्य बिंदु:

- **आयुष मंत्रालय** ने न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया जिसमें दिखाया गया कि SLA ने फरवरी 2022 में दायर एक शिकायत पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिये कहने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की, हालाँकि कंपनी ने पूरे दो वर्षों तक विज्ञापन देना जारी रखा।
- पतंजलि के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि यह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट (DMRA) की धारा 3 का उल्लंघन है, जो **54 बीमारियों और स्थितियों के लिये दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध** लगाता है।
- अधिनियम उन **दवाओं और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध** लगाता है जो चमत्कारी गुणों का दावा करते हैं तथा ऐसा करना अपराध है।
- अधिनियम **"चमत्कारी उपचार"** को परिभाषित करता है जिसमें **यंत्र/ताबीज़, मंत्र, कवच** और ऐसी अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जो रोगों के उपचार के लिये अलौकिक या **चमत्कारी गुणों** का दावा करती हैं।

'आयुष' का अर्थ

- स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक व गैर-पारंपरिक पद्धतियों में **आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा** एवं **होम्योपैथी** आदि शामिल हैं।
- भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ **विविधता** सहित **महत्त्वपूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन** करती हैं।
- ये पद्धतियाँ जन-आबादी के एक व्यापक वर्ग के लिये **अत्यधिक सुलभ और किफायती** हैं।
- पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में, इन पद्धतियों में **अपेक्षाकृत कम लागत** आती है।
- ये **बढ़ते आर्थिक मूल्य** को प्रदर्शित करती हैं, आबादी को एक बड़े हिस्से के लिये महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के रूप में सेवा करने की अपनी क्षमता को उजागर करते हैं।

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष

चर्चा में क्यों ?

बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी के कारण उत्तराखंड के नैनीताल एवं पौड़ी ज़िलों में सुदूरवर्ती ग्रामवासियों को प्रवासन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य ग्राफ में उतार-चढ़ाव हो रहा है।

मुख्य बिंदु:

- पिछले एक दशक में, उत्तराखंड में बड़े वन्य जीवों के कारण **264 लोगों की जान चली गई**, जिनमें से **203 मौतों के लिये** तेंदुए और **61 मौतों के लिये** बाघ जिम्मेदार हैं।
- इन वन्यजीव **घटनाओं ने प्रभावित क्षेत्रों में बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया है**, जिसके कारण स्कूल बंद हो गए हैं और सावलदेह, पटरानी, ढेला एवं **पौड़ी** जैसे गाँवों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
- राज्य सरकार ने **देश के पहले मानव-वन्यजीव संघर्ष-शमन कक्ष** की स्थापना की, **प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा** देने के लिये विशेष धन आवंटित किया और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। हालाँकि, स्थिति अभी भी अस्थिर है।
- **वन्यजीव हमलों ने क्षेत्र में चुनावी घटनाओं को प्रभावित किया है।** वर्ष 2022 में टिहरी में, स्थानीय लोगों ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने से इनकार कर दिया, जो कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान **पौड़ी** में की गई कार्रवाइयों को दर्शाता है।

नोट :

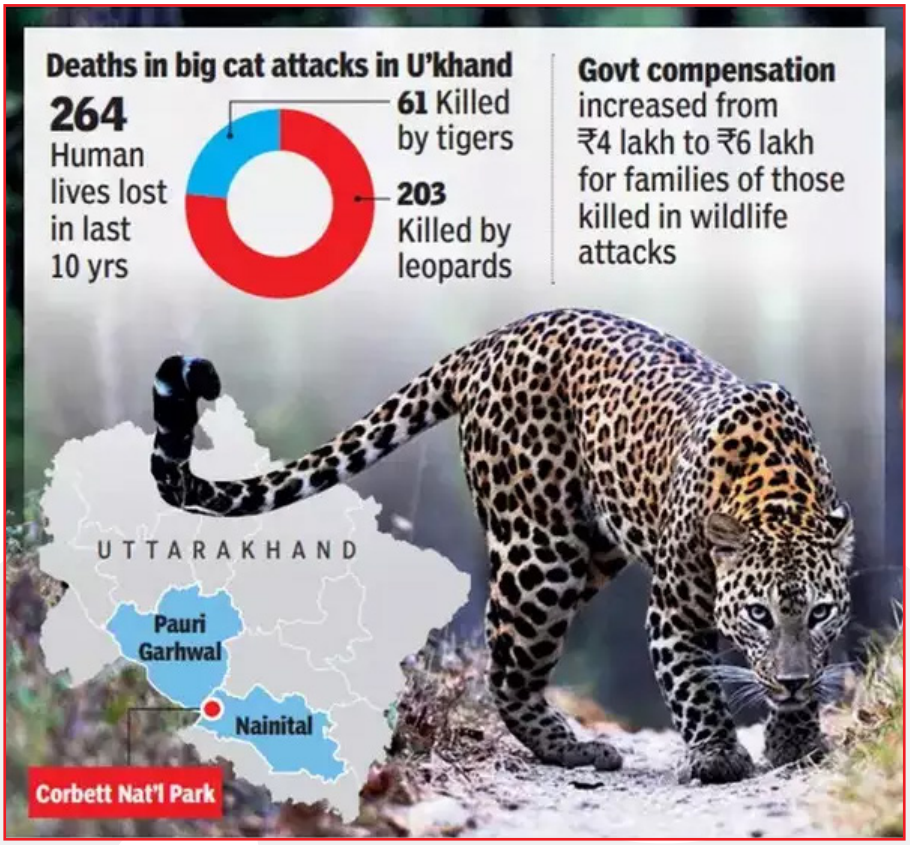

मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- कृषि संबंधी विस्तार
- शहरीकरण
- अवसंरचनात्मक विकास
- जलवायु परिवर्तन
- वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- खेतों और फसलों को नुकसान
- जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)

- समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

राज्य-विशिष्ट पहलें

- **उत्तर प्रदेश-** मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- **उत्तराखंड-** क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- **ओडिशा-** जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

बाघ

	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जब्ती	10	7	13

हाथी

	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
ट्रेनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2

वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

नोट :

चारधाम यात्रा

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अनुसार, 'चारधाम यात्रा' के लिये पर्यटन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में चार मंदिरों, **बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री** के दर्शन शामिल हैं।
- चारधाम यात्रा हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्त्व रखती है। यह यात्रा सामान्यत: **अप्रैल/मई से अक्तूबर/नवंबर** तक होती है।

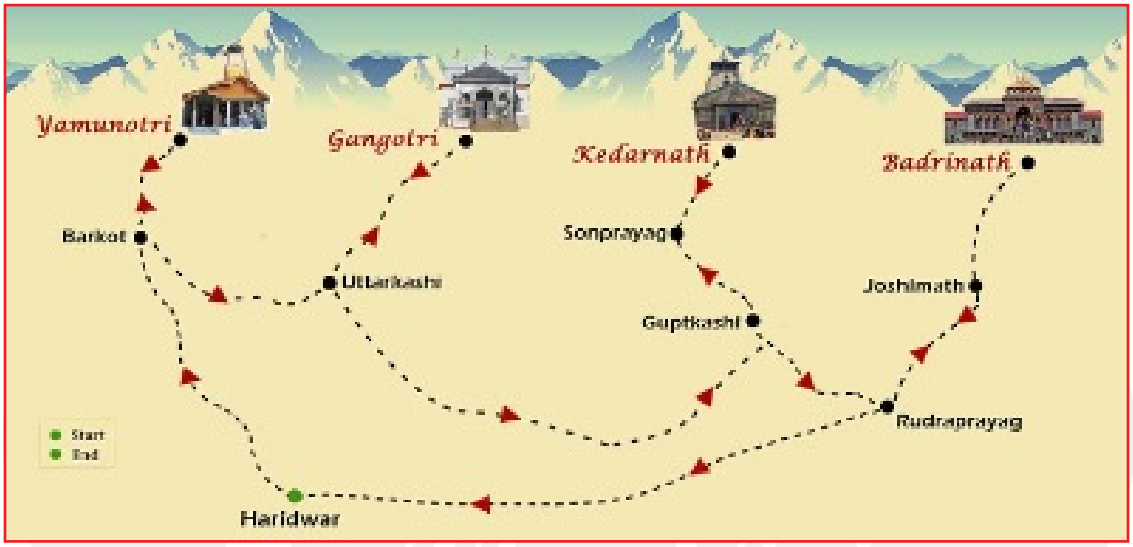

चारधाम यात्रा

- **यमुनोत्री धाम:**
  - **स्थान:** उत्तरकाशी ज़िला।
  - **समर्पित:** देवी यमुना।
  - **गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है।**
- **गंगोत्री धाम:**
  - **स्थान:** उत्तरकाशी ज़िला।
  - **समर्पित:** देवी गंगा।
  - **सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है।**
- **केदारनाथ धाम:**
  - **स्थान:** रुद्रप्रयाग ज़िला।
  - **समर्पित: भगवान शिव।**
  - **मंदाकिनी नदी** के तट पर स्थित है।
  - **भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व) में से एक।**
- **बद्रीनाथ धाम:**
  - **स्थान:** चमोली ज़िला।

नोट :

- **पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का स्थान।**
- **समर्पित: भगवान विष्णु।**
- **वैष्णवों के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक।**

सीमा पार आवागमन पर रोक

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों ने भारत के आम चुनावों से पहले नियमित एहतियात के तौर पर 19 अप्रैल की शाम से भारत में उत्तराखंड राज्य और नेपाल के सुदुरपश्चिम प्रांत के बीच सीमा को अस्थायी रूप से बंद करने की योजना बनाई है।

- **बंद का सीमा पार** आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य बिंदु:

- पूरे भारत में **सुरक्षा बढ़ाई जाएगी** और सीमा के दोनों ओर **कड़ी सतर्कता** बरती जाएगी।
- बंद हटने के बाद **सीमा पार माल ढुलाई और यात्री यातायात** में व्यवधान कई दिनों तक बढ़ सकता है क्योंकि परिवहन कंपनियाँ तथा सीमा शुल्क अधिकारी अपने बैकलॉग को साफ कर रहे हैं।

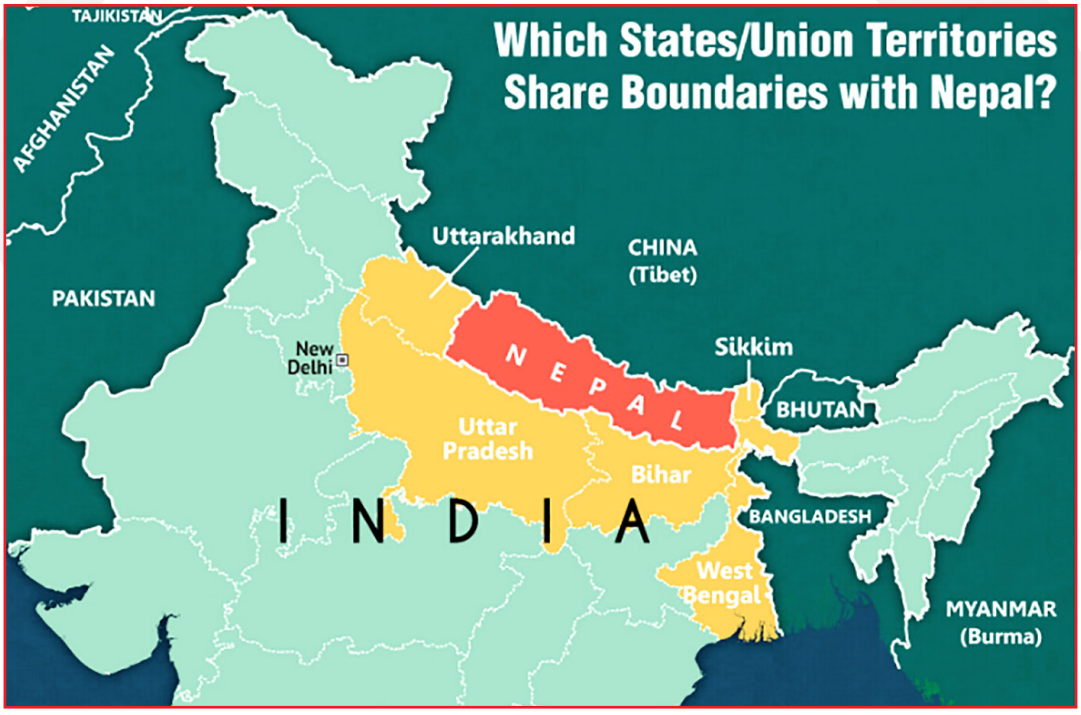

भारत-नेपाल

- नेपाल की **सीमा 5 भारतीय राज्यों**- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार से सीमा साझा करती है। इसलिये सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान का एक महत्त्वपूर्ण बिंदु है।
- भारत के लिये महत्त्व का अध्ययन **दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से** किया जा सकता है:
  - भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये उनका रणनीतिक महत्त्व।
  - अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका धारणा में उनका स्थान।

नोट :

- नेपाल भारत की **'हिमालयी सीमाओं'** के ठीक बीच में है और भूटान के साथ, यह उत्तरी **'सीमावर्ती' पार्श्व** के रूप में कार्य करता है तथा चीन के किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ मध्यवर्ती राज्य के रूप में कार्य करता है।
- नेपाल से निकलने वाली नदियाँ पारिस्थितिकी और जलविद्युत क्षमता के संदर्भ में **भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों का निर्वहन** करती हैं।
- कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल नेपाल में हैं जो इसे बड़ी संख्या में भारतीयों के लिये एक **महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल** बनाते हैं।

उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने उत्तराखंड में हिमालय की ऊपरी गंगा क्षेत्र में एक जलविद्युत परियोजना के पुनर्निर्माण के लिये पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो वर्ष 2013 में बड़े पैमाने पर हुए फ्लैश फ्लड के दौरान लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जिसमें 6,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

मुख्य बिंदु:

- नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के लिये मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने फाटा ब्यूंग जलविद्युत परियोजना (76 मेगावाट) को संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference- ToR) के अनुदान को मंज़ूरी दे दी।
- फाटा ब्यूंग परियोजना ने **मंदाकिनी नदी** के प्रवाह को अवरुद्ध करके **वर्ष 2013 में** बादल फटने (Cloudburst) और **फ्लैश फ्लड** से होने वाली क्षति को और भी बढ़ा दिया।

मंदाकिनी नदी

- यह उत्तराखंड में **अलकनंदा** नदी **की एक सहायक नदी** है।
- यह नदी **रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग** क्षेत्रों के बीच लगभग 81 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है तथा चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है।
- मंदाकिनी सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी में विलीन हो जाती है और **उखीमठ में मध्यमहेश्वर मंदिर के पास से बहती** है।
- अपने मार्ग के अंत में यह अलकनंदा में गिरती है, जो **गंगा** में मिल जाती है।

उत्तराखंड में हताहत-मुक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं। उत्तराखंड की सभी पाँच लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल 2024 को एक ही चरण में मतदान होना है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने **आपातकालीन सेवा के लिये दो हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था** की है और मतदान हताहत-मुक्त होगा जिसमें **कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं** होगी।
- पहाड़ी राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये राज्य भर में 11,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।
  - **वोटों की गिनती 4 जून 2024 को** होनी है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव

- **परिचय:**
  - यह अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करती है जहाँ प्रत्येक पाँच वर्ष पर सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनावों के साथ-साथ संपन्न होंगे
  - विचार यह है कि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए, जिससे समय तथा संसाधनों की बचत होगी

नोट :

- **पृष्ठभूमि:**
  - यह विचार **वर्ष 1983 से ही अस्तित्त्व में** है, जब **निर्वाचन आयोग** ने पहली बार इसे पेश किया था। हालाँकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक सामान्य परिदृश्य रहा था
    - लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित कराए गए थे
    - यह अभ्यास वर्ष 1957, 1962 और 1967 में आयोजित अगले तीन आम चुनावों में भी जारी रहा।
  - लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय-पूर्व विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया
    - वर्ष 1970 में स्वयं लोकसभा का समय-पूर्व विघटन हो गया और वर्ष 1971 में नए चुनाव आयोजित कराए गए। इस प्रकार, वर्ष 1970 तक केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा ने पाँच वर्ष का नियत कार्यकाल पूरा किया

उत्तराखंड में सद्भावना सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरिद्वार में 'हर की पैड़ी' के बाएँ तट पर, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने दो दिवसीय 'सद्भावना सम्मेलन' का आयोजन किया।

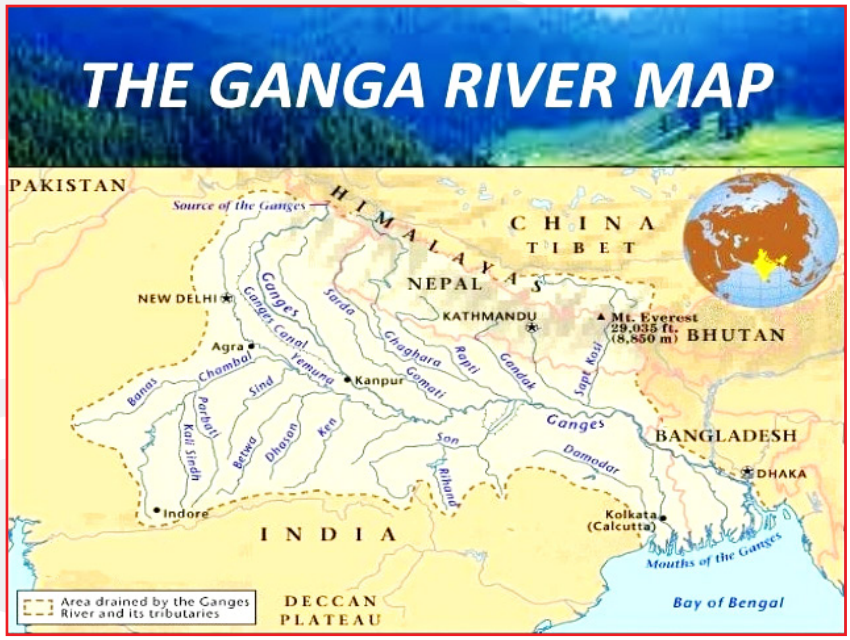

- सम्मेलन में हज़ारों लोग एकत्र हुए, जिसमें मंत्री ने **आध्यात्मिकता और हिंदुओं के लिये गंगा के महत्त्व** पर बात की।

मुख्य बिंदु:

- **उत्तरी और पूर्वी भारत में 2,600 किलोमीटर** से अधिक की दूरी पर बहने वाली गंगा को देवी माना जाता है तथा यह हिंदुओं के लिये धार्मिक आस्था का केंद्र है
  - यह नदी छह राज्यों तथा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच एक केंद्रशासित प्रदेश में फैले **गंगा नदी बेसिन** में रहने वाली भारत की 1.4 अरब जनसँख्या में से 40% से अधिक के लिये **पीने के जल का स्रोत है।**
- **जल शक्ति मंत्रालय** के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 30 लाख लीटर सीवेज प्रतिदिन गंगा में बहाया जाता है और उसमें से केवल आधा ही उपचारित किया जाता है।
  - फेकल/मल कोलीफॉर्म **बैक्टीरिया का एक समूह है** जो **उष्ण रक्तीय जीव-जंतुओं की आँत और मल** में पाया जाता है तथा इसका संदूषण मानव मल पदार्थ की उपस्थिति का संकेत देता है।
  - अनुमान है कि अकेले पवित्र शहर वाराणसी में प्रतिदिन नदी के किनारे 4,000 शव जलाए जाते हैं।
  - उत्तराखंड में बाँध नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे गर्मी के महीनों के दौरान कई स्थानों पर नदी धारा में बदल जाती है।
  - राज्य में जलविद्युत परियोजनाएँ ज़्यादातर नदी प्रवाह (ROR) पर आधारित हैं, सिवाय **टिहरी बाँध परियोजना** के, जो जलविद्युत विकास के लिये एक भंडारण परियोजना है और गैर-मानसूनी नदी के प्रवाह को बढ़ाती है।

नोट :

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, नदी के किनारे 97 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 59 के नमूनों के परीक्षण में जनवरी 2023 में 70% स्थानों पर नदी में **मल कोलीफॉर्म** अनुमेय स्तर से ऊपर था।
- वर्ष 2024 में, नमामि गंगे योजना, नदी को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिये विविध हस्तक्षेपों ने नदी में "प्रदूषण भार" को कम कर दिया।
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बाहरी स्नान मानदंडों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अनुमोदित कार्य योजनाओं के माध्यम से **प्रदूषित नदी खंडों का कायाकल्प** किया जा रहा था।

नमामि गंगे कार्यक्रम

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में **केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था,** ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय **के तहत संचालित किया जा रहा है।**
- यह **कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)** और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम (2021-26) के दूसरे चरण** में राज्य परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने और गंगा के सहायक शहरों में परियोजनाओं के लिये विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - छोटी नदियों और **आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।** प्रत्येक प्रस्तावित गंगा ज़िले में कम-से-कम 10 आर्द्रभूमि हेतु वैज्ञानिक योजना और स्वास्थ्य कार्ड विकसित करना है तथा उपचारित जल एवं अन्य उत्पादों के पुन: उपयोग के लिये नीतियों को अपनाना है।

उत्तराखंड में रिकॉर्ड 55% मतदान

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में पाँच लोकसभा सीटों पर लगभग 55.01% मतदान हुआ, जिसमें वर्ष 2019 के चुनावों में 61.4% की तुलना में 6.3% वोटों (अनुमानित) की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

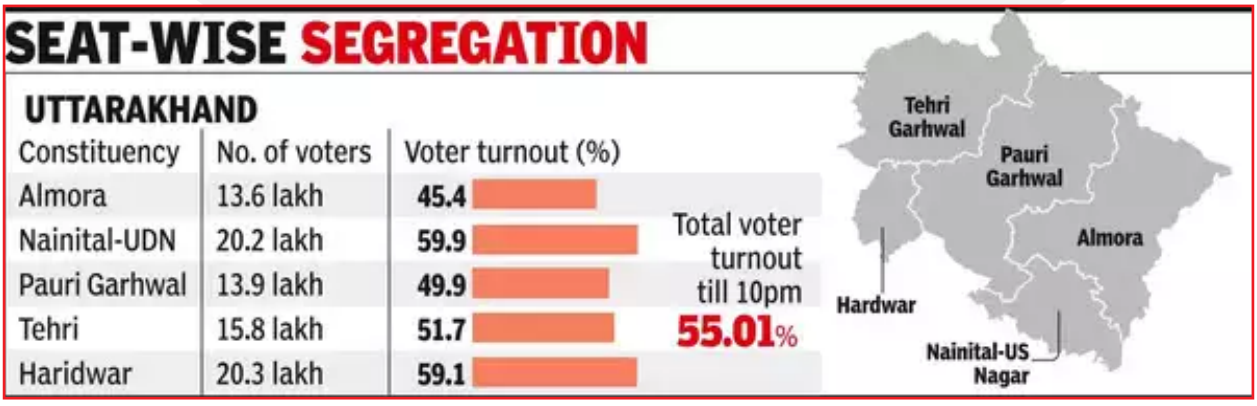

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2024 के चुनावों में सभी **पाँच निर्वाचन क्षेत्रों** में मतदाताओं की भागीदारी में गिरावट देखी गई।
- अल्मोडा में सबसे कम 45.4% मतदान हुआ, सबसे अधिक मतदान नैनीताल-उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र में 59.9% हुआ। इसके बाद हरिद्वार में 59.7%, टिहरी में 51.7%, पौरी गढ़वाल में 49.9% और SC आरक्षित सीट पर हुआ। भारत के आधिकारिक निर्वाचन आयोग ऐप की रिपोर्ट के अनुसार, अल्मोडा में 45.4% है।

नोट :

- उत्तराखंड में **83.2 लाख सामान्य मतदाता** और इसके अलावा **93,357 सेवा मतदाता** हैं।

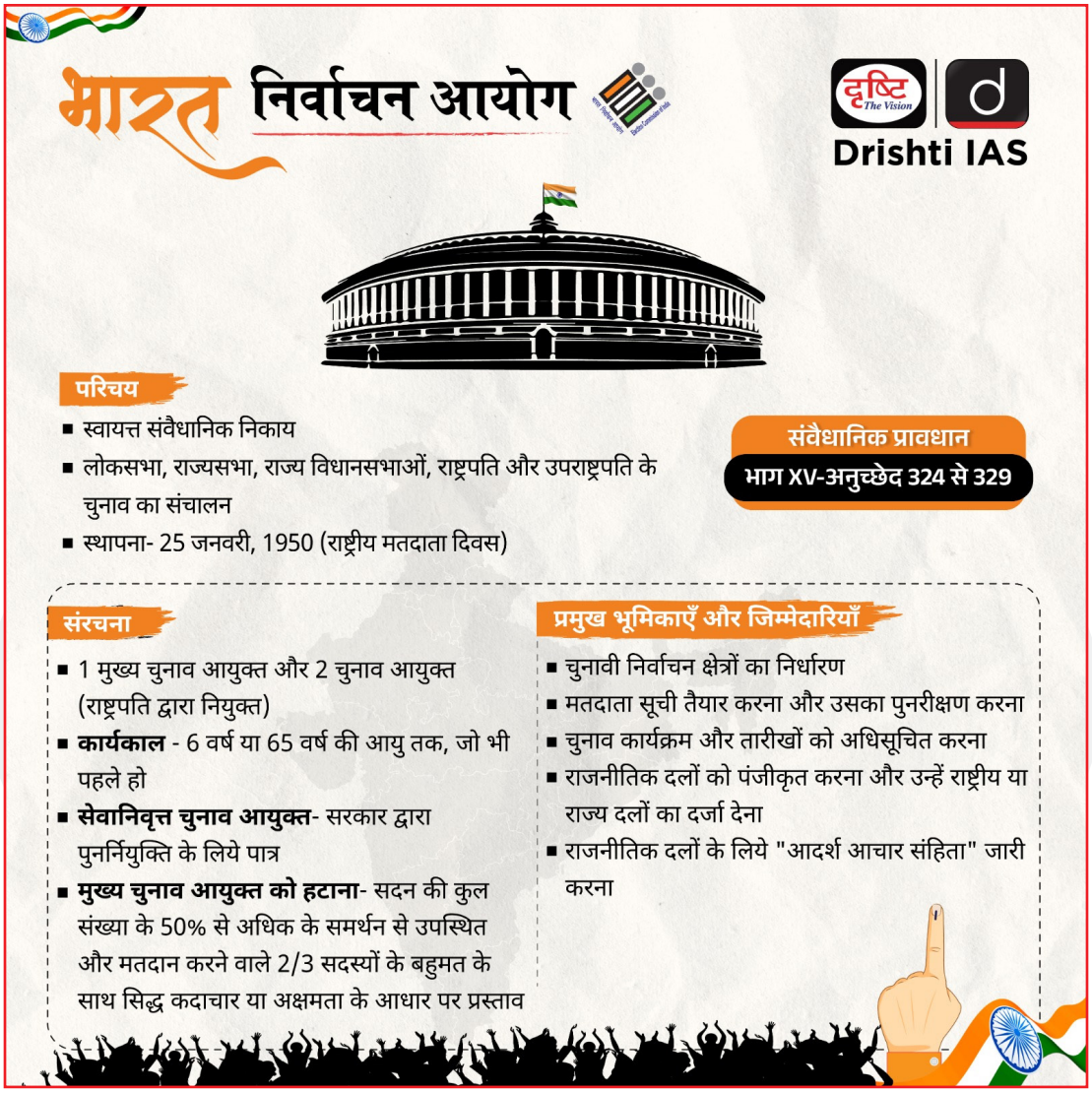

वोटर टर्नआउट ऐप

- **चुनावों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और मतदान के दिन मतदाताओं की उपस्थिति** के बारे में तुरंत जानकारी प्रदान करने के लिये **भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 18 अप्रैल 2019** को यह एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था।
- वोटर टर्नआउट एप का उपयोग प्रत्येक **विधानसभा क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन** क्षेत्र में पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सहित **रियल टाइम वोटर टर्नआउट विवरण** को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है। इस एप का उपयोग नागरिकों द्वारा लाइव वोटर टर्नआउट डाटा कैप्चर करने के लिये किया जा सकता है।
- वोटर टर्नआउट एप नागरिकों को प्रत्येक राज्य के लिये अलग-अलग अनुमानित मतदाता प्रतिशत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है। यह एप **उपयोगकर्ताओं को** अपने संपर्क के लोगों को फेसबुक, ट्विटर, जीमेल और वाट्सएप के जरिये **मतदान प्रतिशत साझा करने की भी सुविधा देता है।** यानी रियल टाइम मतदान के प्रतिशत को कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया एकाउंट में शेयर भी कर सकता है।

नोट :

- **वोटर टर्नआउट एप में कोई डेटा पहले से फीड नहीं किया जा सकता है।** वोटर टर्नआउट एप को प्रत्येक राज्य के लिये अनुमानित वोटर टर्नआउट दिखाने के लिये डिजाइन किया गया है और इसका प्रयोग ज़िला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक किया जा सकता है। मतदान के दिन इस पर राज्यवार, ज़िलेवार और विधानसभा क्षेत्रवार वोटर टर्नआउट का अपडेट देखा जा सकता है।

उत्तराखंड में देहरादून हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू

चर्चा में क्यों ?

इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने के एक महत्त्वपूर्ण प्रयास में, उत्तराखंड सरकार देहरादून को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने पर कार्य कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार ने देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे **और काठमांडू** के बीच सब्सिडी वाली नॉन-स्टॉप उड़ानों के लिये एयरलाइंस से प्रस्ताव मांगे हैं।
  - रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र सरकार भारत की वैश्विक पर्यटन स्थल बनने की क्षमता का लाभ उठाने की इस पहल का समर्थन करती है।
  - **वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटक आगमन (Foreign Tourist Arrival-FTA) कुल लगभग 1.1 करोड़ था। वर्ष 2022 में यह संख्या घटकर 62 लाख हो** गई लेकिन **वर्ष 2023 में** यह बढ़कर **92.4 लाख** हो गई।
  - उद्योग **अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाकर,** नए पर्यटन मार्गों को शुरू करने और **वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर** वर्ष 2019 FTA स्तरों को पार करने की रणनीतियों पर चर्चा कर रहा है।
- **इंडिगो और टाटा ग्रुप एयर इंडिया** जैसी प्रमुख एयरलाइनों के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण केंद्रों के साथ भारत को एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये महत्त्वाकांक्षी रणनीतियाँ चल रही हैं।
- **नेपाल और उत्तराखंड की राजधानी शहरों को जोड़कर,** यह प्रयास न केवल ऐतिहासिक संबंधों को मज़बूत करता है बल्कि **पर्यटन, वाणिज्य तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान** हेतु नए रास्ते भी खोलता है।
- **भारत ने वर्ष 2014 के बाद से हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी कर दी है** और उनमें से कई को कम-से-कम नज़दीकी जलग्रहण देशों से सीधी उड़ानें प्राप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा।

उत्तराखंड की मानसखंड कॉरिडोर यात्रा

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय रेलवे के सहयोग से कुमाऊँ क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को लोकप्रिय बनाने के लिये 'मानसखंड कॉरिडोर यात्रा' शुरू करेगा।

मुख्य बिंदु:

- तीर्थयात्रा के लिये यात्रियों को **पुणे से पिथौरागढ़ ज़िले के टनकपुर** तक ले जाने के लिये एक समर्पित ट्रेन सेवा की व्यवस्था की गई है।
  - ट्रेन **दो बैचों में 600 से अधिक तीर्थयात्रियों** को '**मानसखंड**' के प्रसिद्ध मंदिरों तक ले जाएगी, जो **प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र को संदर्भित करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश है।**
- टूर पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को **टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा** के मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थानों पर ले जाया जाएगा तथा **इन मंदिरों के पौराणिक महत्त्व** के बारे में जानकारी दी जाएगी।
- चंपावत में **बालेश्वर, मनेश्वर एवं मायावती** मंदिरों के दर्शन, हाट कालिका, **पिथौरागढ में पाताल भुवनेश्वर मंदिर, चितई में जागेश्वर तथा गोलू देवता मंदिर, नंदा देवी, कसार देवी, अल्मोडा में कटारमल, उधम सिंह नगर में नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा** और **नैना देवी मंदिर के दर्शन नैनीताल में तीर्थयात्रियों के लिये यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा हैं।**

नोट :

कुमाऊँ क्षेत्र

- इसमें राज्य के छह ज़िले शामिल हैं: **अल्मोडा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथोरागढ़ और उधम सिंह नगर।**
- ऐतिहासिक रूप से **मानसखंड और फिर कुर्मांचल** के रूप में जाना जाने वाला कुमाऊँ क्षेत्र इतिहास के दौरान कई **हिंदू राजवंशों द्वारा शासित** रहा है।
- **कुमाऊँ मंडल की स्थापना वर्ष 1816 में हुई थी,** जब अंग्रेज़ों ने गोरखाओं से इस क्षेत्र को पुन: प्राप्त किया था, जिन्होंने वर्ष 1790 में कुमाऊँ के तत्कालीन साम्राज्य पर कब्ज़ा कर लिया था।
- स्वतंत्र भारत में राज्य को उत्तर प्रदेश कहा जाता था। **वर्ष 2000 में,** कुमाऊँ सहित **उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया।**

राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय उत्तराखंड की यात्रा पर रहेंगी।

मुख्य बिंदु:

- उनकी यात्रा के दौरान:
  - राष्ट्रपति **ऋषिकेश में गंगा आरती और एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।**
  - वह **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी,** देहरादून में **भारतीय वन सेवा (2022 बैच)** के अधिकारी प्रशिक्षुओं के **दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगी।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)

- इसकी **स्थापना वर्ष 1956** में **संसद के एक अधिनियम द्वारा** राष्ट्रीय महत्त्व के एक संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य इसकी सभी शाखाओं में **स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न** विकसित करना था ताकि भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानक को प्रदर्शित किया जा सके।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य गतिविधि की सभी महत्त्वपूर्ण शाखाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिये उच्चतम क्रम की शैक्षिक सुविधाओं को एक स्थान पर लाना और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी

- यह **भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत** एक वन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जो मूल रूप से भारतीय वन कॉलेज के रूप में था, जिसे वरिष्ठ वन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये **वर्ष 1938 में स्थापित किया गया था।**
- यह **वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के नये वन परिसर में स्थित है।**

चिपको आंदोलन के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वर्ष 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड में शुरू हुआ चिपको आंदोलन अपनी 50वीं वर्षगाँठ मना रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह एक **अहिंसक आंदोलन** था जो **वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले (अब उत्तराखंड)** में शुरू हुआ था।
- आंदोलन का नाम 'चिपको' 'आलिंगन' शब्द से आया है, क्योंकि ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगाया और उन्हें काटने से बचाने के लिये घेर लिया

नोट :

- इस आंदोलन का नाम '**चिपको**' '**वृक्षों के आलिंगन**' के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिये उनके चारों और मानवीय घेरा बनाया गया।
- जंगलों को संरक्षित करने हेतु **महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण** के लिये इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया।
- इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों को जंगलों पर उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था और कैसे ज़मीनी स्तर की सकि्रयता पारिस्थितिकी तथा साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है।
- इसकी सबसे बड़ी जीत **लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक करना** तथा यह समझाना था कैसे ज़मीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिकी और **साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है।**
  - इसने **वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1,000 msl** (माध्य समुद्र तल-msl) से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया।

भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन

नाम	वर्ष	स्थान	प्रमुख	विवरण
बिशनोई आंदोलन	1700	राजस्थान का खेजड़ी, मारवाड़ क्षेत्र	अमृता देवी	
चिपको आंदोलन	1973	उत्तराखंड	सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट	खेजड़ी (जोधपुर) राजस्थान में वर्ष 1730 के आस-पास अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर उनको बचाने के लिये आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली, उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था।
साईलेंट वैली प्रोजेक्ट	1978	केरल में कुंतीपुझा नदी	केरल शास्त्र साहित्य परिषद सुगाथाकुमारी	केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट कुद्रेमुख परियोजना के तहत कुंतीपुझा नदी पर एक पनबिजली बाँध के निर्माण के विरुद्ध था।

नोट :

जंगल बचाओ आंदोलन	1982	बिहार का सिंहभूम ज़िला	सिंहभूम की जनजातियाँ	यह आंदोलन प्राकृतिक साल वन को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ था।
अप्पिको आंदोलन	1983	कर्नाटक	लक्ष्मी नरसिम्हा	प्राकृतिक पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये। सागौन और नीलगिरि के पेड़ों के व्यावसायिक वानिकी के खिलाफ।
टिहरी बाँध	1980-90	उत्तराखंड में टिहरी पर भागीरथी और भिलंगना नदी	टिहरी बाँध विरोधी संघर्ष समिति, सुंदरलाल बहुगुणा और वीरा दत्त सकलानी	
नर्मदा बचाओ आंदोलन	1980 से वर्तमान तक	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	मेधा पाटकर, अरुंधती राय, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आम्टे	

उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड वन विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में अब तक राज्य में वनाग्नि की 477 घटनाएँ सामने आई हैं, जिसमें 379.4 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को नुकसान पहुँचा है।

मुख्य बिंदु:

- क्षतिग्रस्त हुई **379.4 हेक्टेयर** भूमि में से 136.4 हेक्टेयर गढ़वाल क्षेत्र में, **202.82 हेक्टेयर कुमाऊँ क्षेत्र में और 40.2 हेक्टेयर प्रशासनिक वन्यजीव क्षेत्रों** में क्षतिग्रस्त हुई।
- वन अधिकारियों के अनुसार वनाग्नि एक वार्षिक समस्या बन गई है और मौसम की स्थिति में बदलाव के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड में **फरवरी के मध्य में वनाग्नि** का अनुभव शुरू होता है जब **पेड़ों के सूखे पत्ते गिर जाते हैं और तापमान में वृद्धि के कारण मृदा में नमी कम हो जाती है** तथा यह जून के मध्य तक जारी रहता है।
- वर्ष 2000 से, जब राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, अब तक वनाग्नि से 54,800 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

वनाग्नि

- **इसे बुश फायर/वेजिटेशन फायर या वनाग्नि भी कहा जाता है,** इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि (Shrubland) अथवा टुंड्रा में पौधों/वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है तथा पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे- हवा तथा स्थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता है।
- वनाग्नि के लिये तीन कारकों की उपस्थिति आवश्यक है और वे हैं- ईंधन, ऑक्सीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत।

नोट :

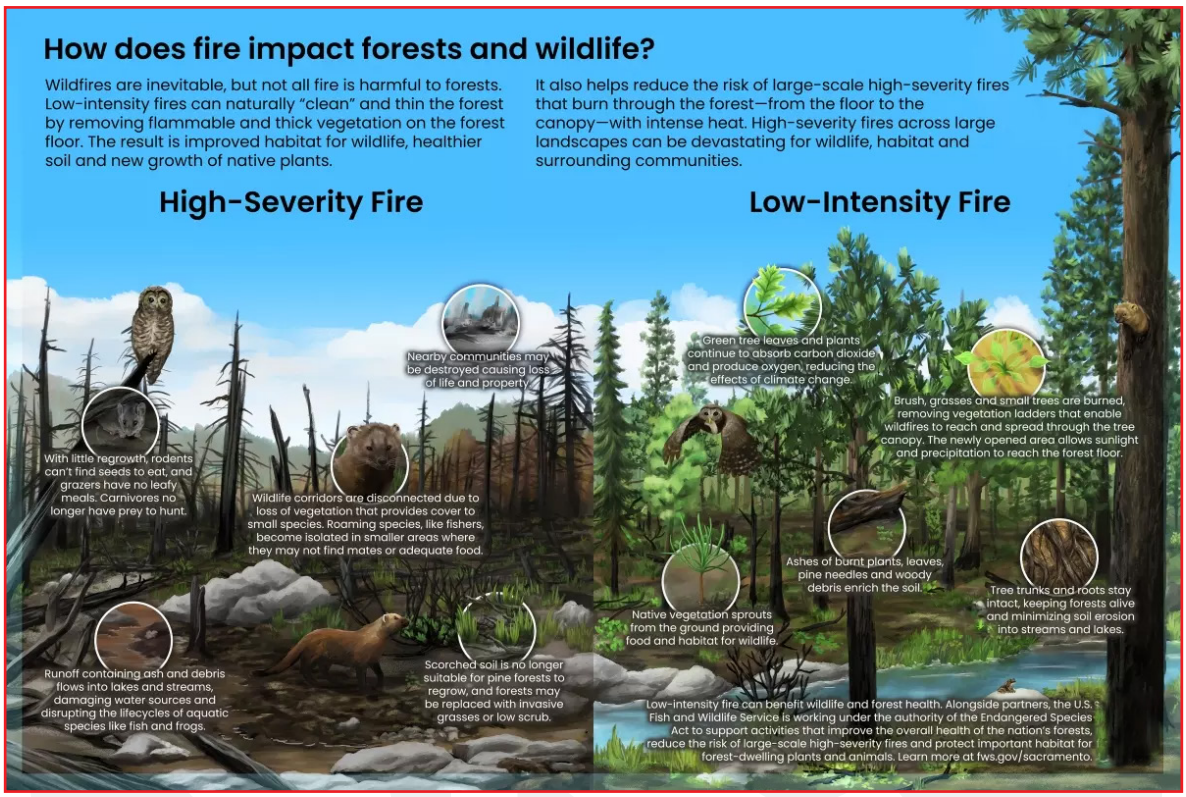

उत्तराखंड में पिघलते ग्लेशियर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के पिथोरागढ़ ज़िले में रणनीतिक रूप से मुनस्यारी-मिलम सड़क के किनारे जौहर घाटी की ओर एक ग्लेशियर स्खलन/फिसलने की घटना हुई, जिससे भारत-चीन सीमा और क्षेत्र के गाँवों का संपर्क प्रभावित हुआ।

मुख्य बिंदु:

- सीमा सड़क संगठन (BRO) ने सड़क साफ करने के प्रयास शुरू कर दिये हैं लेकिन व्यापक बर्फबारी के कारण चुनौतियाँ बरकरार हैं।
  - विशेषज्ञ इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ग्लेशियर का टूटना जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों की स्पष्ट चेतावनी देता है।
  - ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हिमालय क्षेत्र को बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तेज़ी से ग्लेशियर पिघलना भी शामिल है।
- मार्च 2024 में पिथौरागढ़ के ऊपरी क्षेत्रों में **हिमपात** देखी गई थी। अब तापमान बढ़ने के साथ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे हिम-स्खलन हो रहा है और कभी-कभी हिमखंड भी टूट रहे हैं।

सीमा सड़क संगठन

- BRO की परिकल्पना और स्थापना **वर्ष 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू** द्वारा देश के **उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों** में सड़क निर्माण में तेज़ी से विकास के समन्वय के लिये की गई थी।
- यह **रक्षा मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- इसने निर्माण एवं विकास कार्यों के स्तर में व्यापक विविधता ला दी है, जिसमें **हवाई क्षेत्र, निर्माण परियोजनाएँ, रक्षा कार्य और सुरंग बनाना शामिल है** तथा जनता के प्रति काफी लोकप्रिय है

नोट :

उत्तराखंड मॉनसून वर्षा के लिये तैयार

चर्चा में क्यों ?

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, उत्तराखंड में वर्ष 2024 के मानसून में सामान्य से अधिक बारिश के लिये राज्य सरकार को तैयारी शुरू कर देनी चाहिये।

मुख्य बिंदु:

- **उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA)** द्वारा मानसून तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के लिये एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
- अधिकारियों के मुताबिक **मौसम विभाग** लगातार मौसम संबंधी जानकारी को लेकर अलर्ट भेजता रहता है और अगर उसका पालन किया जाए तो आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा जान-माल के नुकसान को भी कम किया जा सकता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग

- IMD की स्थापना **वर्ष 1875 में** हुई थी। यह **देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है** और मौसम विज्ञान तथा संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में **प्रमुख सरकारी एजेंसी है।**
- यह **भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका **मुख्यालय नई दिल्ली** में है।
- IMD, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के **छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों** में से एक है।

नैनीताल में वनाग्नि

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में नैनीताल के निकट वनों में भीषण आग फैल गई। संकट ने भारतीय वायु सेना को भीषण आग पर काबू पाने में सहायता के लिये कर्मियों और Mi-17 हेलीकॉप्टरों को भेजने के लिये प्रेरित किया।

वनाग्नि ने कथित तौर पर 108 हेक्टेयर वन को नष्ट कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- **बांबी बकेट ऑपरेशन** के नाम से जाने जाने वाले ऑपरेशन में आग बुझाने के लिये हेलीकॉप्टर जल इकट्ठा कर रहे हैं और जेट-स्प्रे का उपयोग कर रहे हैं।
- **उत्तराखंड के वन विभाग** के मुताबिक, **राज्य के** कुमाऊँ क्षेत्र में कुछ ही घंटों में वनाग्नि की 26 घटनाएँ हुईं।
  - जबकि **पाँच घटनाएँ गढ़वाल क्षेत्र में हुईं** जहाँ 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ।
- भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले **वन अनुसंधान संस्थान** की **वर्ष 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **95% वनाग्नि मनुष्यों के कारण होती है।**
- **भारत में वनाग्नि के चार समूह हैं:** उत्तर-पश्चिमी हिमालय, उत्तर-पूर्वी भारत, मध्य घाट और पश्चिमी एवं पूर्वी घाट।
  - **उत्तर-पश्चिमी हिमालय** में वनाग्नि का कारण **चीड़ के पेड़ों की बहुतायत और घने ज्वलनशील अपशिष्ट का जमाव है।**
  - गर्मियों के दौरान वन में भारी मात्रा में चीड़ की तीक्ष्ण-नुकीली पत्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं, जो आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और वनाग्नि का कारण बनती हैं।

बांबी बकेट ऑपरेशन

- बांबी बकेट, जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेलीबकेट भी कहा जाता है, एक विशेष कंटेनर है जिसे एक हेलिकॉप्टर के नीचे केबल द्वारा लटकाया जाता है और जिसे **आग के ऊपर प्रवाहित करने से पहले नदी या तालाब में उतारा जा सकता है तथा बकेट के नीचे एक वाल्व खोलकर हवा में छोड़ा जा सकता है।**

नोट :

- बांबी बकेट विशेष रूप से वनाग्नि से बचने या उसका सामना करने में सहायक है, जहाँ ज़मीन से पहुँचना मुश्किल या असंभव है। विश्व भर में वनाग्नि का सामना करने के लिये अक्सर हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है।

वनाग्नि

- **इसे बुश फायर/वेजिटेशन फायर या वनाग्नि** भी कहा जाता है, इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि (Shrubland) अथवा टुंड्रा में पौधों/वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है तथा पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे- हवा तथा स्थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता है।
- वनाग्नि के लिये **तीन कारकों की उपस्थिति** आवश्यक है और वे हैं- **ईंधन, ऑक्सीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत।**
- **वर्गीकरण:**
  - **सतही आग:** वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग (Surface Fire) के रूप में होती है जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ जल जाती हैं तथा धीरे-धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं।
  - **भूमिगत आग:** कम तीव्रता की आग, जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है, को भूमिगत आग के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश घने जंगलों में **खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है।**
- इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत रूप में फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक जलती है।
- यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश मामलों में इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
- ये कई महीनों तक जलते रह सकते हैं और मृदा से वनस्पति तक के आवरण को नष्ट कर सकते हैं।
  - **कैनोपी या क्राउन फायर:** ये तब होता है **जब वनाग्नि पेड़ों की ऊपरी आवरण/वितान के माध्यम से फैलती है**, जो प्राय: तेज़ हवाओं और शुष्क परिस्थितियों के कारण भड़कती है। ये विशेष रूप से तीव्र और नियंत्रित करने में कठिन हो सकती हैं।
  - **कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर:** कुछ मामलों में, कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर, जिसे **निर्धारित वनाग्नि या झाड़ियों की आगजनी के रूप** में भी जाना जाता है, इच्छित तौर पर या जानबूझकर वन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा ईंधन भार को कम करने, अनियंत्रित **वनाग्नि के जोखिम को कम करने** और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये लगाई जाती है।
  - जोखिमों को कम करने और वन पारिस्थितिकी तंत्र को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिये इन नियंत्रित अग्नि की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है तथा विशिष्ट परिस्थितियों में निष्पादित किया जाता है।

उत्तराखंड ने पतंजलि उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु रामदेव की दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये उनके विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं।

मुख्य बिंदु:

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने हाल के सप्ताहों में अपनी कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने हेतु चल रहे मुकदमे में अपने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये रामदेव की बार-बार आलोचना की है।
- जिन 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किये गए, उनमें **अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और मधुमेह** की पारंपरिक दवाएँ शामिल थीं।
- सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उन आरोपों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि पतंजलि पारंपरिक दवाओं की उपेक्षा करती है और न्यायालय के निर्देश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी करती है।

नोट :

- पतंजलि के विज्ञापनों ने **औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम, 1954 (DOMA)** तथा **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (CPA)** का उल्लंघन किया।
- **औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम, 1954,** औषधि विज्ञापनों को नियंत्रित करता है तथा कुछ चमत्कारिक उपचारों के प्रोत्साहन पर प्रतिबंध लगाता है।
  - यह अधिनियम में सूचीबद्ध विशिष्ट व्याधियों के लिये औषधियों के उपयोग का प्रोत्साहन करने वाले और औषधि की प्रकृति अथवा प्रभावशीलता का अनुचित प्रतिनिधित्व करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है।
  - इसके अतिरिक्त यह उन्हीं व्याधियों के उपचार का दावा करने वाले चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।
- **CPA की धारा 89** झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के **लिये कठोर दंड लगाती है।**
  - इसमें कहा गया है कि कोई भी **निर्माता या सेवा प्रदाता** जो किसी गलत या भ्रामक विज्ञापन का कारण बनता है, जो उपभोक्ताओं के हित के लिये हानिकारक है, उसे दो वर्ष की अवधि के लिये कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो **दस लाख रुपए तक का हो सकता है** और प्रत्येक उत्तरोत्तर अपराध के लिये पाँच वर्ष की अवधि के लिये कारावास की सज़ा दी जाएगी।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :